SHRI G. VISWANATHAN: Will the Finance Minister consider increasing grants and loans to a State like Madras which is doubling food production and while collecting interest on the loans given to States will the Finance Minister assure us that he will not behave like a stingy money-lender and will comply with the requests of the State Governments?

SHRI MORARJI DESAI: I will not act as a stingy moneylender but I hope the State will not act as a bankrupt.

SHRI VIRBHADRA SINGH: I want to know whether due to the re-organisation of Punjab any loan liability of composite Punjab has been transferred to Himachal Pradesh and, if it has been, what is the amount involved.

SHRI MORARJI DESAI: If a separate question is asked, I will certainly give the figures.

श्री सरजू पांडेय : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो राज्यों को पैसा दिया जाता है उस में खास तौर से उन के रेवेन्यू पर ही ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि उन की जरूरतों को भी देखा जाता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों को लोन देते समय सरकार उनकी फाइनेंशल पोजीशन का असेसमेंट कर लेती है या सिर्फ जरूरत के आधार पर ही दे देती है ?

श्री मोरारजी देसाई : वह भी करते हैं ।

CONSUMER CONSULTATIVE COUNCIL FOR PUBLIC UNDERTAKINGS

*814. **SHRI PREM CHAND VERMA**: Will the Minister of FINANCE be pleasead to state:

(a) whether it is a fact that the Administrative Reforms Commission has recommended the appointment of a Consumer Consultative Council for products of Public Undertakings;

(b) if so, whether Government have taken any steps to implement this recommendation; and

(c) the composition, functions and terms of reference of the Council and the criteria for selection of its members?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): (a) and (c). The Administrative Reforms Commission, in their Report on "Public Sector Undertakings", have recommended that Consumers' Consultative Council should be set up in each sector of public enterprise. These Councils, according to the Commission, should consist of the representatives of organised bodies of consumers concerned with the products of the enterprise, the controlling Ministry, the sector corporation concerned and other interested Government departments and Public Enterprises. It has also been recommended that Parliament may elect two members to serve on each of these Councils. The Councils are to deal with the matters involving the interest of the consumers and further advise Government or sector Corporations on such matters as may be referred to them by the latter.

(b) The recommendation is under consideration of the Government.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या यह सत्य है कि पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ जो माल तैयार करती हैं उन में कन्ज्यूमर इन्टरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता है और न ही इन्टरनेशनल प्राइस का ध्यान रखा जाता है । जैसाकि सरकार को मालूम होगा कि हैवी इलैक्ट्रिकलज़ भोपाल से बम्बई की एक फर्म ने कैपेसिटर्स मांगे थे, उसकी कीमत उन्होंने 1 करोड़ 14 लाख रुपये बतलाई, जब कि विदेशों से आनेवाले कैपेसिटर्स की कीमत 20.18 लाख रुपये है, इस तरह से पांच गुनी कीमत हिन्दुस्तान की बनी हुई चीज़ की ज्यादा है । इस तरह से कन्ज्यूमर इन्टरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाता है ।

दूसरे—क्या यह भी ठीक है कि जो माल हमारी पब्लिक या प्राइवेट अण्डरटेकिंग्ज़

बनाती हैं, उनकी इम्पोर्ट बन्द कर दी जाती है, जिससे कन्ज्यूमर इम्पोर्ट नहीं कर सकता और उस को मजबूरन यहां पर चार गुनी या पांच गुनी कीमत देनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में क्या सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जहां तक कन्ज्यूमर इन्टरेस्ट का सवाल है, इस बात का बराबर ख्याल रखा जाता है। जहां तक कीमतों में अन्तर का सवाल है, उस के अलग अलग कारण हो सकते हैं—जिसकी वजहसे अन्तर हो सकता है। जहां तक इम्पोर्ट बन्द करने का सवाल है, वह तो होना ही चाहिए, जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। इसी वजह से हमारी यह नीति है कि जो चीजें देश में पैदा होती हैं, उनकी इम्पोर्ट बन्द कर देनी चाहिये।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या यह सच नहीं है कि ब्यूरो आफ़ पब्लिक एन्टरप्राइजेज़ इस वक्त केवल पोस्ट आफिस का काम कर कर रहा है। क्या सरकार इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिये, इस को फिर से रिओर्गेनाइज़ करने के लिये, इस को ज्यादा अख्तियार देने के लिये किसी कार्यवाही पर विचार करेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह कहा गया है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है।

NATIONAL INCOME

*815. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the rate of growth of the National Income and per capita income during the first year of the Fourth Five Year Plan;

(b) whether it is a fact that the growth has been far below the targets fixed in the draft outline of the Fourth Five Year Plan and also less than the achievements during the Third Five Year Plan; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to increase per capita income?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : (a) The 'Quick Estimate' of national income for 1966-67 prepared by the Central Statistical Organisation shows an increase of 1.7 per cent in real terms over the preceding year. Due to the population increase, the per capita income, however, is estimated to show a decline of 0.7 per cent.

(b) and (c). The slow rate of growth in 1966-67, which was below the targets fixed in the draft outline of the Fourth Five Year Plan and also less than the achievements in the Third Plan, was primarily due to the continued drought conditions affecting agricultural and other production. The better harvests of 1967-68 are expected to result in a substantial increase in national and per capita income. Efforts will continue to be made to increase agricultural and other production further to secure further increases in per capita incomes.

श्री सीताराम केसरी : क्या यह सही है कि हमारे देश में पर-कैपिटा इन्कम के गिरने का कारण मन्दी है ? क्या यह भी सत्य है कि विदेशों से जो सहायता आती थी, उस के अभाव के कारण आपने चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा को प्रस्तुत करने में विलम्ब किया है ? हमारी राष्ट्रीय इन्कम का पचास फीसदी कृषि से आता है—मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है, जिससे कि हमारे कृषि के उत्पादन बढ़ें ताकि उन के द्वारा हमारी आमदनी बढ़ सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उत्पादन बढ़ाने के लिये हर प्रकार की कोशिश हो रही है। जहां तक मन्दी का सवाल है, पर-कैपिटा इन्कम कम होने की वजह मन्दी नहीं है। मन्दी होने की वजह ही इन्कम में कमी है। जहां तक फोर्थ प्लान का ताल्लुक है—जिन एज़म्पशन्ज़ पर फोर्थ प्लान बनाया गया था, उस में कई परिवर्तन हो गये—डिवैल्यूएशन के कारण सूखे के कारण दामों के बढ़ने